जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 134 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 20 मार्च, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

प्र.मंत्री मोदी दो दिन की यात्रा पर आर.एस.एस. के मुख्यालय जायेंगे, 24 व 25 मार्च को

मोदी दस साल में पहली बार, प्र.मंत्री बनने के बाद, आर.एस.एस. मुख्यालय जायेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मार्च। प्रधानमंत्री मोदी, सरसंघ चालक मोहन भागवत से दूरियां मिटाने के लिए 24 व 25 मार्च को दो दिवसीय यात्रा पर नागपुर जा रहे हैं। गत दस सालों में जब से मोदी के नेतृत्व में भाजपा केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है, पहली बार मोदी संघ मुख्यालय जा रहे हैं। सूत्रों ने इसे मोदी और भागवत के बीच ''सीज़फायर'' बताया।

सूत्रों ने बताया कि सरकार के शुरुआती दिनों में संघ नेता चर्चा के लिए रेसकोर्स रोड आया करते थे, पर, फिर उस पर रोक लगा दी गई।

दोनों के बीच गहरी खाई रही है। इतनी कि दोनों ही भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एक-दूसरे की पसंद को अस्वीकार कर रहे हैं और यह निर्णय अभी भी लंबित है। भाजपा, केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में आर.एस.एस. अपनी चलाना चाहती है।

- इस यात्रा को जानकार लोग ''मोदी व भागवत के बीच ''सीज़फायर'' की संज्ञा दे रहे हैं। क्योंकि प्र.मंत्री मोदी व संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच दूरियां काफी चर्चित हो गई थी तथा दोनों एक-दूसरे से कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। विशेषकर ऐसे मुद्दे पर भी कि नया भाजपा अध्यक्ष कौन बने।
- कई विवादास्पद मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि सितम्बर में मोदी 75 वर्ष के हो जायेंगे, तब वे रिटायरमैंट लेंगे, संघ व पार्टी की स्थापित परम्परा के अनुसार या यह सिद्धांत उन पर लागू नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मोदी की रिटायरमैंट की तारीख से एक सप्ताह पूर्व ही मोहन भागवत भी 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके होंगे। ऐसी हालत में 75 की उम्र पार करने के बाद कोई भी नेता संगठन व पार्टी किसी भी पद से रिटायरमैंट ले लेंगे, इस सिद्धांत का क्या होगा।
- ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर मोदी-भागवत की बैठक में चर्चा होगी तथा कोई ठोस निर्णय उभरने की आशा है।

बताया जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर अंततः भाजपा को संघ की पसंद देवेन्द्र फड़नवीस को स्वीकार करना ही पड़ा था।

भाजपा नेता कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को जो 240 सीटें मिली है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि चुनावों में संघ ने भाजपा का पूर्ण सहयोग नहीं किया और यही सच्चाई भाजपा नेतृत्व को संघ के दरवाजे पर ले गई है।

सूत्रों ने यह बताने के लिए मोदी और भागवत के बीच ''सीज़फायर'' शब्द का इस्तेमाल किया है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें प्रमुख है भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। मोदी के अगले मंत्रिमंडल में फेरबदल में किसे शामिल किया जाए, किसे हटाया जाए? आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका होगी? सितम्बर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद का रोड मैप क्या होगा? उसके 6 दिन पहले भागवत भी 75 के हो जाएंगे।

क्या दोनों नेताओं के बीच सहमति बनेगी। दोनों टकराव के रास्ते पर चलते रहेंगे, जैसे गत कुछ वर्षों से चल रहे हैं। सभी की नज़रें इन दोनों की मीटिंग पर ही है।

9 माह बाद धरती पर कदम रखे सुनीता विलियम्स ने

फ्लोरिडा, 19 मार्च। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू-9 के दो और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैशडाउन हुआ, यानी पानी में लैंडिंग हुई। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार (18 मार्च) को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस

- नासा ने सुनीता व उनके साथियों की सफल वापसी के लिए एलन मस्क की कम्पनी स्पेसऐक्स को धन्यवाद दिया।

हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। हालांकि, ऐसा होना आम बात है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पृथ्वी पर लौटे। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण किया है। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स को धन्यवाद दिया।

एक तरफ भारत के बाँग्लादेश से रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है

दूसरी ओर चीन ने बाँग्लादेश में वित्तीय व मैडिकल मदद के लिये सारे दरवाजे खोले

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मार्च। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में बाँग्लादेश के बारत के बिगड़ते हुये सम्बंधों के चलते, चीन ने बाँग्लादेश में अपना निवेश जबरदस्त मात्रा में बढ़ा दिया है।

जहाँ भारत इलाज के लिये भारत आने की इच्छा रखने वाले बाँग्लादेशियों के मामले में सख्ती बरत रहा है, वहीं एक चीनी अधिकारी ने यह कहा बताते हैं कि चीन दक्षिण -पश्चिमी राज्य यूनान में मेडिकल टूरिज़्म मार्केट की संभावनाएं तलाश रहा है। चीन के इस कदम का लक्ष्य बाँग्लादेशी ही हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि जब से नोबल लॉरिएट मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार बनी है, उसके बाद 14 चीनी कम्पनियाँ बाँग्लादेश में 230 मिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुकी हैं। बाँग्लादेश के वास्तविक प्रधानमंत्री, यूनुस इस माह के अन्त में चीन यात्रा पर जाने वाले हैं, जहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन ढ़ाका में एक फ्रेन्डशिप हॉस्पीटल खोलने पर विचार कर रहा है, ताकि बाँग्लादेशी वहाँ निशुल्क इलाज करा सकें। जहाँ तक यूनुस का प्रश्न है, उन्होंने ऑनरिकॉर्ड यह बात कही है कि बाँग्लादेश अपना बाजार चीन के लिये खोल देने के लिये तैयार है। इससे पूर्व, एक शीर्ष चीनी सोलर एनर्जी कम्पनी बाँग्लादेश में अपना कार्यालय शुरु करने तथा मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश करने के लिये सहमत हो गई है।

- भारत, उदाहरण के लिये बाँग्लादेश से ईलाज के लिये आने वाले लोगों को वीज़ा देना काफी कम करता जा रहा है और अब प्रतिदिन 1,000 से कम वीज़ा जारी किये जा रहे हैं, जबकि रिश्तों में तनाव आने से पूर्व, रोज 5,000 से 7,000 वीज़ा जारी होते थे।
- दूसरी, चीन ढ़ाका में एक ''फ्रेंडशिप हॉस्पीटल'' खोलने की बात कर रहा हैं, बाँग्लादेशियों के लिये।
- साथ ही, खासकर, बाँग्लादेशियों के लिये, ''मैडिकल टूरिज़्म'' को प्रोत्साहित कर रहा है चीन तथा चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में, युन्नान को मैडिकल टूरिज़्म का ''हब'' बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- वित्तीय आदान-प्रदान की दृष्टि से चीन की 14 कंपनियों ने बाँग्लादेश में 230 मिलियन डॉलर इनवेस्ट किये हैं, जब से, मोहम्मद युनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनी है।
- युनूस ने भी चीन को विश्वास दिलाया है कि बाँग्लादेश अपना मार्केट पूर्णतया खोल देगा, चीने में निर्मित माल बेचने के लिये।

पिछले कुछ महीनों में, भारत ने बाँग्लादेशियों को प्रतिदिन 1000 मेडिकल वीसा से भी कम वीसा दिये हैं, जबकि शेख हसीना के शासनकाल में 5000-7000 वीसा प्रतिदिन दिये जाते थे। हसीना गत वर्ष अगस्त के बाद भारत में रह रही हैं तथा उन पर मुकदमा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संघ ने ''औरंगज़ेब'' मसले पर हुई हिंसा से दूरी बनाई

संघ के प्रवक्ता ने अधिकृत रूप से कहा कि छठा मुगल बादशाह औरंगज़ेब, जिसकी 300 साल पहले मृत्यु हुई थी, आज ''इररैलेवैंट'' (महत्वहीन) हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मार्च। औरंगज़ेब के मकबरे को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के दौर में एक गंभीर कदम उठाते हुए संघ ने खुद को इससे अलग कर लिया है। भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा छठा मुगल बादशाह आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है।

हालांकि संघ खुद को हिंदु-मुसलमान मुद्दे से दूर करने का प्रयास कर रही है पर संघ के राजनैतिक विस्तार भाजपा के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके नेताओं को अक्सर नवजीवन प्रदान करता है। जाने माने विशेषज्ञों का सवाल है कि संघ ने जिस जिन्न को बोतल से बाहर निकाला था क्या उसे पुनः बोतल में बंद किया जा सकता है।

- कर्नाटक में 21 तारीख से आयोजित ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा के एजेंडा की जानकारी देते समय संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिये ''अनहैल्दी'' (हानिकारक) है।
- उनसे जब सीधा पूछा गया कि क्या आज मृत्यु के तीन सौ साल बाद, औरंगज़ेब का कुछ महत्व है तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, ''बिल्कुल नहीं।''

उत्तर प्रदेश में कुछ माह पूर्व जब संभल मस्जिद विवाद उठा था तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद कर देना चाहिए। पर तब संघ से जुड़े संगठनों विहिप, बजरंगदल आदि ने भागवत की आलोचना की थी।

ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा जिसका आयोजन कर्नाटक में 21 से 23 मार्च को हो रहा है, से पहले संघ के संचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि किसी भी किस्म की हिंसा समाज के लिए घातक है और आज के दौर में औरंगज़ेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने औरंगज़ेब का मकबरा, जो नागपुर से 500 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर में है, को हटाने की मुहिम से अप्रत्यक्ष रुप से इन्कार का संकेत दिया और शांति व सद्भावना बनाए रखने की बात कही।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थप्पड कांड के आरोपी नरेश मीणा को अभी रिहाई नहीं

जयपुर, 19 मार्च राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय उम्मीदवार रहे आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका को

- राजस्थान हाई कोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जो एस.डी.एम. को थप्पड़ मारने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, की जमानत याचिका खारिज कर दी।

खारिज कर दिया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील महेश शर्मा ने कहा कि प्रकरण साधारण मारपीट का है, जबकि याचिकाकर्ता कई माह से न्यायिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग संस्थान'

'विद्यार्थी ने पढ़ाई बीच में छोड़ी तो दस दिन में बकाया फीस लौटानी होगी'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 19 मार्च। भजनलाल सरकार ने कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने के लिए बुधवार को राज्य विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025' पेश किया। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक सदन के पटल पर रखा। अब इस पर चर्चा होगी। बिल पास होने पर कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। पिछले सप्ताह प्रदेश में कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण और विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा देने की मंशा से मंत्रिमंडल की बैठक में यह बिल मंजूर किया गया था।

उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा ने कहा कि कोचिंग छात्रों के अभिभावकों की शिकायतें व लगातार हो रही आत्म हत्या की घटनाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता से लिया, इसलिए हम कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाए हैं। इसमें जिला स्तरीय कमेटी बनाने का प्रावधान भी है और

- कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने के लिये राज्य विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सैंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 पेश किया।
- बिल में प्रावधान है कि कानून लागू होते ही तीन माह के अंदर कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वरना कोचिंग संस्थान बंद कर दिया जायेगा।
- कोचिंग संस्थानों पर निगरानी के लिए एक राज्यस्तरीय अथॉरिटी गठित होगी, उसके अधीन हर जिले में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भी अथॉरिटी गठित होगी।
- रजिस्ट्रेशन की शर्ते पूरी नहीं करने पर कोचिंग संस्थान को पहली बार में दो लाख रूपए, दूसरी बार में 5 लाख रूपए जुर्माना देना होगा। तीसरी बार में कोचिंग संस्थान बंद कर दिया जाएगा।

राज्य स्तर पर भी कमेटी बनाएंगे। कोचिंग संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई होगी व बार-बार गलती करने पर कोचिंग संस्थान को बंद किया जा सकता है।

बैरवा ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति ठीक रहे, व्यक्तित्व का अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण लाने का यह पहला प्रयास है, जो कमियां रहेंगी, उन्हें दूर करेंगे।

कानून आने के बाद, छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा। अधिनियम के लागू होने के पश्चात कोई भी कोचिंग सेंटर वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना संचालित नहीं होगा। अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

कोई भी कोचिंग संस्थान अगर रजिस्ट्रीकरण की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उस पर पहली बार में 2 लाख रुपए व दूसरी बार में 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा और तीसरी बार में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन होगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। अथॉरिटी के अधीन हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामले में तीन कॉंस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर, 19 मार्च। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपरलीक मामले में एसओजी ने कार्यवाही करते हुए तीन पुलिस कांस्टेबल सहित एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है।

- वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, 13 नवम्बर 2021 को आयोजित हुई थी। इस दौरान सांवला राम जाट के घर पर उसकी महिला मित्र शारदा पुत्री नगाजी भील सहित छह लोगों को पेपर पढ़ाया गया था।

एसओजी की टीम चारों आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार कर बांसवाड़ा ले जा रही है। एसओजी के एडी. डी.जी.पी.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ईडी पिछले दस साल में केवल दो राजनीतिज्ञों को अपराधी करार करा सकी है''

कनिष्ठ वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह लिखित जानकारी दी, एक प्रश्न के उत्तर में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मार्च। मोदी सरकार ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि एनफोर्समैंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) ने अब तक जिन 193 राजनेताओं के खिलाफ, जाँच के बाद, केस दर्ज किये हैं, उनमें से केवल दो राजनेताओं पर ही दोष सिद्ध हुये हैं।

यह जानकारी आज जूनियर वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक सांसद द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

इससे पूर्व, एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 25 विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस, उनके भाजपा में शामिल होने के बाद वापस ले लिये गये थे। इन नेताओं में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तथा असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वा सरमा सहित अन्य कई नेता शामिल हैं।

दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

- जानकारी में यह भी कहा गया कि अब तक 193 मामले राजनीतिज्ञों के खिलाफ दर्ज किये हैं ईडी ने।
- पहला ''कनविक्शन'' आदेश ईडी ने 2016-17 में तथा दूसरा ''कनविक्शन'' 2019-20 में प्राप्त किया था।
- मंत्री ने अपने जवाब में यह भी लिखा कि सबसे ज्यादा ईडी के मामले (59 मामले) 2022-24 के बीच दर्ज किये गये थे, जबकि लोकसभा के 2024 चुनाव सिर पर थे।
- जैसा कि विदित ही है, ईडी की कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी गत नवम्बर में ईडी मामलों में इतनी कम ''कनविक्शन'' होने पर टिप्पणी की थी तथा ईडी को अपनी जाँच पर और फोकस करने की सलाह दी जिससे ''कनविक्शन'' रेट बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में यह पूछा था कि किसी भी व्यक्ति को कितने दिन तक ''ट्रायल'' पर रखा जा सकता है।

सहित अन्य नेता कथित शराब घोटाले के सिलसिले में जेल भेज दिये गये थे।

चौधरी ने अपने जवाब में लिखा, ''सांसदों, विधायकों तथा स्थानीय नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केसों के आँकड़े राज्य-वार एवं पार्टी-वार संधारित नहीं किये गये हैं। चौधरी के उत्तर में 1 अप्रैल, 2015 से 28 फरवरी, 2025 के बीच ईडी द्वारा राजनेताओं के खिलाफ दर्ज केसों का ब्यौरा वार्षिक आधार पर दिया गया है।

सर्वाधिक 32 केस वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज हुये, उसके बाद 2020-21 तथा 2023-24 में प्रत्येक वर्ष में 27 केस तथा 2019-20 एवं 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 26 केस दर्ज हुये।

जूनियर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की संवीक्षा बताती है कि ईडी अधिकारियों की कार्यवाहियों में नरेन्द्रमोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उछाल आया। दूसरे कार्यकाल की उस अवधि में खासतौर से ज्यादा केस दर्ज किये गये, जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने को थे। 2022 से 2024 के बीच 59 केस दर्ज किये गये।

मंत्री द्वारा दिये गये वर्ष-वार ब्रेकअप के अनुसार, एक राजनेता 2016-17 में तथा एक 2019-20 में दोषी पाया गया था।

पिछले कुछ वर्षों में, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो सहायक- ज्योतिप्रिय मलिक तथा अणुव्रत मंडल आदि। इनके अलावा, कई अन्य तृणमूल विधायक भी गिरफ्तार किये गये।

चटर्जी के अलावा, इनमें से अधिकांश नेताओं को जमानत मिल चुकी है। एजेंसी कथित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

18 पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि मंजूर की मुख्यमंत्री ने

जयपुर, 19 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान निधि दिए जाने को मंजूरी दी। इन्हें राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार योजना के तहत सम्मान निधि दी जाएगी। इन आवेदनकर्ता पात्र पत्रकारों के नामों की

- राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत इन पत्रकारों को प्रतिमाह 15 हज़ार रूपए दिए जाएंगे।

अनुशंसा जनसम्पर्क विभाग की विभागीय समिति ने की थी।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह 15 हजार रुपए सम्मान निधि प्रदान की जाती है। साठ वर्ष की आयु से अधिक जिन कुल 18 वरिष्ठ पत्रकारों को यह सम्मान निधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)